SUSHANT UNIVERSITY ORGANIZED INTERNATIONAL CONFERENCE ON
"ADVANCES IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNVOATION" ICAMRI-2023
ON 28-29TH OCTOBER 2023
INTERNATIONAL ADVANCE JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMENT (IAJESM)
July-December 2023, Submitted in October 2023, iajesm2014@gmail.com, ISSN -2393-8048
Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 =6.753

धन निष्कासन का भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

Dr. Rajkumar, Assistant Professor, Department of History, Seth G.L. Bihani S.D. Post Graduate, Sriganganagar

सारांश

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से किए गए सुनियोजित धन निष्कासन (Drain of Wealth) के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह अवधारणा सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, और एम.जी. रानाडे जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने यह तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की आर्थिक समृद्धि धीरे-धीरे क्षीण होती गई क्योंकि देश की संपत्ति निरंतर इंग्लैंड स्थानांतरित की जा रही थी।

इस शोध में धन निष्कासन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया गया है जैसे—कच्चे माल का सस्ता निर्यात, तैयार माल का महंगा आयात, ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाने वाली तनख्वाह और पेंशन, तथा 'होम चार्जेस' के नाम पर की गई आर्थिक निकासी। इन सभी माध्यमों से भारत से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की संपत्ति विदेश भेजी गई, जिसके परिणामस्वरूप भारत में औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ, कृषि संकट बढ़ा, और व्यापक गरीबी व बेरोजगारी ने जन्म लिया।

शोध यह दर्शाता है कि किस प्रकार धन निष्कासन ने भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को एक निर्यात-आधारित, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था में बदल दिया, जो ब्रिटिश हितों पर केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त, यह भी विश्लेषण किया गया है कि कैसे इस आर्थिक शोषण ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया और राष्ट्रवादी नेताओं के आर्थिक असंतोष को एकजुट किया।

अंततः, यह शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि धन निष्कासन केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक संरचना को प्रभावित करने वाला एक गहन औपनिवेशिक शोषण तंत्र था, जिसने दीर्घकालिक आर्थिक अव्यवस्था और जन-आक्रोश को जन्म दिया।

महत्वपूर्ण शब्द: धन निष्कासन, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, दादाभाई नौरोजी, ब्रिटिश शासन, आर्थिक शोषण, भारत का गरीबीकरण, उपनिवेशीय नीति।